राठौड़ भीमजीभाई मसरुभाई राजपूत व अन्य

बनाम

बॉम्बे राज्य व अन्य

7 दिसंबर, 1959

(एस.के. दास, जे.एल. कपूर और ए.के. सरकार, न्यायाधीशगण)

तालुकदारी कार्यकाल - "लाल-लिटि" भूमि का उन्मूलन - भू-राजस्व के लिए दायित्व - तालुकदारी भूमि - तालुकदारी जागीर - बॉम्बे भू-राजस्व संहिता, I879 (I879 का बॉम्बे V), धारा 136(1)- गुजरात तालुकदार अधिनियम, I888 (I888 का बॉम्बे VI), धारा 4, 5, 22, 31 बॉम्बे तालुकदारी अवधि उन्मूलन अधिनियम, 1949 (I949 का बॉम्बे LXII), धारा 2(3), (4), 3, 5(1)(क),(ख), 5(2)(क) 17(ग)

अपीलकर्ता जो "लाल-लिटि" भूमि के रूप में जानी जाने वाली कुछ भूमि के धारक थे, बॉम्बे तालुकदारी कार्यकाल उन्मूलन अधिनियम, 1949 के लागू होने के बाद, बॉम्बे भूमि राजस्व संहिता, 1879 के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व का मूल्यांकन किया गया था। "लाल-लिटि" भूमि मूल रूप से गुजरात में तालुकदारों द्वारा कैडेटों, परिवार की विधवाओं और रिश्तेदारों को भरण-पोषण के लिए और ग्राम सेवकों और अन्य लोगों को या तो पिछली सेवाओं के इनाम के रूप में या की

जाने वाली सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी। ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले, तालुकदारों के पास अर्ध-स्वतंत्र प्रमुखों की स्थिति थी, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद वे सीधे सरकार से भूमि प्राप्त करने वाली मालिकाना सम्पदा के मालिक बन गए, और ऐसी संपत्तियों के संबंध में उनके राजस्व प्रशासन के लिए गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 पारित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि ब्रिटिश काल से पहले से ही इन जमीनों का उपयोग बिना किसी "जामा" के भुगतान के किया गया था और भू-राजस्व के भुगतान से छूट बॉम्बे तालुकदारी कार्यकाल उन्मूलन अधिनियम, 1949 से प्रभावित नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि भूमि उस अधिनियम की धारा 5 के तहत मूल्यांकन योग्य थी। अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि, अन्य बातों के अलावा, अधिनियम की धारा 5 के तहत "लाल-लिटि" भूमि के संबंध में भू-राजस्व के भुगतान के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि (1) तालुकदार ने ऐसी भूमि में कोई रुचि नहीं रखी है। अनुदान और, परिणामस्वरूप, ऐसी भूमि अधिनियम की धारा 2(3) के अर्थ में तालुकदारी भूमि नहीं थी, (2) अधिनियम की धारा 5(1) का खंड (क) केवल घोषणात्मक था, जबकि खंड (ख) प्रवर्त्तनशील खंड था जिसके द्वारा भूमि राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वो ही थे जो (i) राठौड़ भीमजीभाई के पास कोई तालुकदारी भूमि रखने वाला एक

तालुकदार और (ii) एक तालुकदारी परिवार का एक कैडेट जिसके पास रखरखाव के लिए मसरूभाई राजपूत के लिए कोई भी तालुकदारी भूमि थी, और (3) यहां तक कि यह मानते हुए कि और एक अन्य खंड (क) ने तालुकदारी भूमि को बॉम्बे भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी बना दिया है, एक "लाल-लिटि" धारक को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वह संहिता की धारा 136(1) के अर्थ के अंतर्गत असंक्रमित भूमि का अधिभोगी नहीं था।

अभिनिर्धारित:

(1) कि "लाल-लिटि" भूमि के इतिहास और गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त भूमियां ऐसी भूमियां हैं जो तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा बनती हैं, भले ही वास्तव में कोई "जामा" तालुकदार या सरकार को भुगतान किया जाता था, और इसलिए, बॉम्बे तालुकदारी उन्मूलन अधिनियम, 1949 की धारा 2(3) के अर्थ के तहत तालुकदारी भूमि हैं;

(2) बॉम्बे तालुकदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 5(1) का खंड (क) एक सामान्य प्रावधान था और बॉम्बे भू-राजस्व अधिनियम को सभी तालुकदारी भूमि पर लागू करता था, जबकि खंड (बी) इस संबंध में एक विशेष प्रावधान था। तालुकदार और उसके कैडेटों को; और

(3) बॉम्बे तालुकदारी उन्मूलन अधिनियम द्वारा तालुकदारी अवधि के उन्मूलन पर,

पहले "लाल-लिटि" धारक की स्थिति जो भी रही हो, वह उस भूमि का वास्तविक कब्ज़ा धारक बन गया जिसके संबंध में सरकार ने राजस्व के भुगतान के अपने अधिकारों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में स्थानांतरित नहीं किया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या- 327/1955

विशेष सिविल आवेदन संख्या 1100/1954 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 1955 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील

अपीलार्थी की ओर से: एल.एम. लिमाए, एस.एन.एंडले, जे.बी. दादाचनजी और रामेश्वर नाथ

प्रत्यर्थी की ओर से: एन. पी. नाथवानी, के. एल. हाथी और आर. एच. ढेबर

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एस. के. दास द्वारा दिया गया।

यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 1955 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है जिसके द्वारा इसने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए एक रिट प्रार्थना संख्या-1100/1954) को मय हर्जे खर्चे खारिज कर दिया, जो अब हमारे सामने अपीलकर्ता हैं। यह विचार और निर्णय के लिए कुछ जटिलताओं वाली भू-राजस्व समस्या को उठाता है, जो बॉम्बे तालुकदारी कार्यकाल उन्मूलन अधिनियम,

1949, (1949 का बॉम्बे अधिनियम LXII) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे इसके बाद उन्मूलन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। समस्या यह है कि क्या अपीलकर्ता, कुछ भूमि के धारक जिन्हें "लाल-लीती" भूमि के रूप में जाना जाता है, बॉम्बे भू-राजस्व संहिता, 1879 (1879 का बॉम्बे अधिनियम V) के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं।, उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के बाद, इसे राजस्व संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है।

इस समस्या पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में तालुकदारी कार्यकाल की कुछ घटनाओं के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिवर्तनों के संदर्भ में जिनके माध्यम से उन कार्यकालों में कानून या अन्यथा अतीत में बदलाव हुए थे। इस अपील के प्रयोजनों के लिए गुजरात में तालुकदारी सम्पदा का पूरा इतिहास देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह बताना आवश्यक है कि "लाल-लीती" भूमि का क्या अर्थ है। हमें बैडेन-पॉवेल की "Land-systems of British India" और दांडेकर की "The law of Land Tenure in the Bombay Presidency" जैसी पुस्तकों से मिलता है, जिनमें से दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारे सामने बड़े पैमाने पर उद्धृत किया है, जिसका एक संक्षिप्त इतिहास है गुजरात के तालुकदार और उनकी जागीरें का इतिहास संक्षेप में बताया गया है, इतिहास इस प्रकार है: गुजरात के तालुकदार (वे तब तालुकदार के रूप में नहीं जाने जाते थे,

क्योंकि नाम बहुत बाद में दिया गया था) मूल रूप से प्रमुखों या शासकों के पद पर थे। यह गुजरात में मुसलमानों के शासन से पहले की बात है। जब मुसलमानों ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो उन्होंने पाया कि देश बड़े या छोटे सरदारों की जागीरों में बंटा हुआ है, जिनसे उन्होंने जबरन उनकी संपत्ति का एक-चौथाई हिस्सा छीन लिया, और इस तरह जो हिस्सा बचा, उसे 'वांता' (विभाजित) का नाम दिया गया। कुछ 'वांता' लगान या राजस्व के भुगतान से मुक्त थे; अन्य 'वांता' जागीरें "उदहड जामा" (निश्चित राशि) के रूप में राजस्व दिया करती थीं। मुगलों के बाद मराठा आये। मराठों के विलय और प्रभुत्व से इन अर्ध-स्वतंत्र प्रमुखों की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि मराठा शासन के तहत वार्षिक भुगतान अलग-अलग थे। फिर अंग्रेज़ आये जिन्होंने कुछ समय तक पिछले वर्षों के अनुसार वार्षिक राजस्व वसूलना जारी रखा लेकिन बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और भुगतान की प्रकृति में बदलाव किया गया, और कर के बजाय, सरकार ने इसे किराया या राजस्व माना। किराया या राजस्व में भी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि इन भूमि के धारक आर्थिक शर्मिंदगी में पड़ गए और गरीब और जरूरतमंद हो गए। तब वार्षिक पट्टों की एक प्रणाली शुरू की गई थी: हालाँकि, यह उपचार बीमारी से भी बदतर साबित हुआ, और कानून द्वारा तालुकदारों की स्थिति में सुधार करने की मांग की गई। जब तक हम गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 (1888 का बॉम्बे अधिनियम VI) पर नहीं आते, तब

तक उस कानून के विवरण का उल्लेख करना हमारे उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, जो तालुकदारी कार्यकाल के इतिहास में एक मील का पत्थर था। हमें बाद में इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करने का अवसर मिलेगा। यहां यह बताना पर्याप्त है कि जब तक उपरोक्त अधिनियम पारित किया गया तब तक अहमदाबाद सहित गुजरात के कुछ जिलों के तालुकदार वास्तव में केवल मालिकाना सम्पदा के मालिक बन गए थे, जिनके पास सीधे सरकार से भूमि थी, और अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, उनकी सम्पदा के राजस्व प्रशासन का प्रावधान किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक गांव के लिए बंदोबस्त पंजिका तैयार की गई, जो उन संपत्तियों में अधिकारों के अभिलेख के उद्देश्य को पूरा करते थे। इन सम्पदाओं में, संभवतः तालुकदारों द्वारा कैडेटों, परिवार की विधवाओं और रिश्तेदारों को भरण-पोषण के लिए और ग्राम सेवकों और अन्य लोगों को भूमि के बड़े क्षेत्र या तो पिछली सेवाओं के इनाम के रूप में या की जाने वाली सेवा के पारिश्रमिक के रूप में दिए गए थे। इन हस्तांतरित भूमि के धारकों ने आम तौर पर तालुकदार या सरकार को कोई राजस्व नहीं दिया।· ये अनुदान तीन श्रेणियों में आते हैं: (i) जो ब्रिटिश शासन से पहले दिए गए थे; (ii) जो 1818 और 1888 के बीच, अर्थात ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद और गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 के पारित होने से पहले बनाए गए थे; और (iii) जो 1888 के बाद बनाई गई थीं। इस प्रकार हस्तांतरित की गई भूमि को "लाल-लिटि" भूमि कहा जाता था

क्योंकि वे पुराने 'फैसल पत्रकों' में लाल स्याही में दर्ज की गई थीं और बंदोबस्त रजिस्टरों में भी, वे लाल स्याही में दर्ज की गई थीं लेकिन अलग-अलग विशेषताओं की "जामा" (भूमि राजस्व) देनदारियों के अधीन दिखाया गया है। ब्रिटिश-पूर्व हस्तांतरणों को श्री पेइल (बाद में सर जेम्स पेइल) द्वारा मान्यता दी गई थी, जो 1866 में तालुकदारी निपटान अधिकारी थे, और इन जमीनों के धारकों ने आम तौर पर कोई "जामा" का भुगतान नहीं किया था 1818-1888 के हस्तांतरण वे थे जिन्हें चिरभोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, और जब ये भूमि तालुकदार को वापस कर दी गई, तो वे पूर्ण "जामा" के भुगतान के लिए उत्तरदायी उसकी सामान्य भूमि बन गईं। अधिनियम के बाद के अनुदान को गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 31 द्वारा कवर किया गया था (इस संबंध में डॉ. जी.डी. पटेल द्वारा लिखित "पुनर्गठित बॉम्बे राज्य की भूमि समस्याएं", पृष्ठ 174-175 देखें)।

संक्षेप में, तालुकदारी सम्पदा और "लाल-लिटि" भूमि का इतिहास ऐसा ही है, जहाँ तक उस इतिहास का हमारे सामने मौजूद समस्या पर प्रभाव है। अब उन तथ्यों को बताना आवश्यक है जिन्होंने वर्तमान अपील को जन्म दिया है। उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका में, अपीलकर्ताओं ने कहा कि वे अहमदाबाद जिले के धन्धुका तालुक के खरड़ और राजका गांवों में "लाल-लिटि" भूमि के धारक थे और बिना किसी "जामा" (भू-राजस्व) के भुगतान के भूमि का आनंद ले रहे थे। पूर्व-ब्रिटिश शासन के बाद से, हालांकि जिन परिस्थितियों में उनके पूर्ववर्तियों को मूल

रूप से जमीनें मिलीं, वे प्राचीनता में खो गई हैं। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि भू-राजस्व के भुगतान से जो छूट उन्हें मिलती रही है, वह उन्मूलन अधिनियम या बॉम्बे व्यक्तिगत इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1952 (बॉम्बे अधिनियम LXII, 1953) जैसे किसी भी छोटे कानून से प्रभावित नहीं थी, और यह कि 1950-1953 के लिए बंबई राज्य सरकार द्वारा की गई भू-राजस्व के भुगतान की मांग कानून द्वारा अधिकृत नहीं थी। विकल्प में, उन्होंने यह भी कहा कि वे अगस्त,1953 तक भू-राजस्व के किसी भी मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं थे। तदनुसार, उन्होंने उचित रिट के लिए प्रार्थना की (ए) भूमि राजस्व के भुगतान की मांगों को रद्द कर दिया और (बी) बॉम्बे राज्य, अहमदाबाद के कलेक्टर और धंधुका के राजस्व अधिकारी (जो अब हमारे सामने प्रतिवादी हैं) को निर्देश दिया कि वे ऐसा करने से रोकें। उनके पास मौजूद "लाल-लिटि" भूमि के लिए भू-राजस्व के भुगतान को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया इसी तरह के कई आवेदन, संभवतः "लाल-लिटि" भूमि के अन्य धारकों द्वारा दायर किए गए थे, जो उच्च न्यायालय में भी लंबित थे, जहां तक हम अपने सामने मौजूद अभिलेख से समझ सकते हैं, ऐसे आवेदनों के तीन सेट थे। उच्च न्यायालय ने रिट आवेदन संख्या 1098/1954 पर अपना प्रमुख निर्णय सुनाया और यहां अपीलकर्ताओं के आवेदन (संख्या 1100/1954) को प्रमुख निर्णय में दिए गए आधार पर हर्जे खर्चे के साथ खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से माना कि "लाल-लिटि" भूमि के धारक राजस्व संहिता के प्रावधानों

के साथ पढ़े गए उन्मूलन अधिनियम की धारा 5 के तहत भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, और उनकी ओर से उठाई गई आपत्तियां कानूनी तौर पर वैध नहीं थी संविधान के अनुच्छेद 133(1)(ग) के तहत एक प्रमाण पत्र के लिए अपने आवेदन में असफल होने पर, अपीलकर्ताओं ने आवेदन किया और 29 जून, 1955 को इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की। फिर उन्होंने वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न आधारों पर उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता को चुनौती दी है। इन्हें एक-एक करके लेने में सुविधा होगी।

पहला मुद्दा यह है कि उन्मूलन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान "लाल-लिटि" भूमि पर लागू नहीं होते हैं, जो उन्मूलन अधिनियम के अर्थ में "तालुकदारी भूमि" नहीं हैं, और इसलिए, भू-राजस्व के भुगतान के लिए कोई दायित्व नहीं है। "लाल-लिटि" भूमि के संबंध में उसकी धारा 5 के अंतर्गत विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस स्तर पर, हमें उन्मूलन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। "तालुकदारी भूमि" और "ताल्लुकदारी कार्यकाल" अभिव्यक्तियाँ धारा 2, खंड (3) और (4) में परिभाषित हैं:

धारा 2:

(1).........................(1 क) ....

(2) ....

(3) 'तालुकदारी भूमि' का अर्थ है तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली भूमि और इसमें ऐसी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली भूमि और रखरखाव के उद्देश्य से तालुकदार के परिवार के कैडेट द्वारा रखी गई भूमि शामिल है;

(4) 'तालुकदारी कार्यकाल' का अर्थ उस भूमि का स्वामित्व है जिस पर तालुकदारी भूमि रखी गई है। धारा 3 में कहा गया है: "यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन यह अधिनियम लागू होता है।"

(i) तालुकदारी कार्यकाल जहां कहीं भी मौजूद हो, उसे समाप्त माना जाएगा;

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या उसके तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, तालुकदारी संपत्ति में शामिल किसी भी भूमि से जुड़े उक्त और अन्य स्वामित्व की सभी घटनाओं को समाप्त माना जाएगा।

धारा 5, जो इस अपील के प्रयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1953 में संशोधित होने से पहले इस प्रकार पढ़ी गई थी।

धारा 5 (1) "उपधारा (2) (क) के प्रावधानों के अधीन, सभी तालुकदारी भूमि संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं और होंगी, और

(ख) इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले रखरखाव के उद्देश्य से वंशानुगत रूप से किसी भी तालुकदारी भूमि को रखने वाले तालुकदार या तालुकदारी परिवार के

कैडेट को संहिता के अर्थ के तहत या वर्तमान में लागू कोई अन्य कानून के अंतर्गत एक अधिभोगी माना जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा-

(क) विशेष अनुबंध या किसी तत्समय प्रवर्त किसी कानून के तहत भू-राजस्व के भुगतान से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट वाली किसी भी तालुकदारी भूमि को रखने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार

(ख) किसी भी व्यक्ति को किसी करार या समझौते के तहत "जामा" देने का अधिकार धारा 23 के तहत या तालुकदार अधिनियम की धारा 22 के तहत की गई घोषणा के तहत मान्यता प्राप्त है, जब तक कि ऐसा करार, समझौता या घोषणा इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लागू रहती है।

अब, अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क निम्नलिखित पंक्तियों पर आगे बढ़ा है; उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभिव्यक्ति "तालुकदारी भूमि" को तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है; लेकिन अभिव्यक्ति "तालुकदारी संपत्ति" को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि अभिव्यक्ति "तालुकदारी कार्यकाल" को परिभाषित किया गया है; इसलिए, तालुकदारी संपत्ति का मतलब केवल ऐसी भूमि या संपत्ति हो सकता है जिसमें तालुकदार का कुछ निहित हित हो; लेकिन "लाल-लिटि" भूमि में, कम से कम पूर्व

-ब्रिटिश शासन में, अनुदान के बाद तालुकदार का कोई हित नहीं रहता है, और इसलिए उन्मूलन अधिनियम की धारा 5 के अर्थ में "लाल-लीती" भूमि तालुकदारी भूमि नहीं है। अब हमें तर्क की इस पंक्ति की सार्थकता पर विचार करना होगा।

उच्च न्यायालय में और हमारे समक्ष भी उत्तरदाताओं की ओर से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि यदि धारक की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है, तो तालुकदार के पास "लाल लिती" भूमि पर प्रत्यावर्ती अधिकार बरकरार रहता है। उच्च न्यायालय ने हमारी राय में सही कहा कि उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाताओं ने वह स्थिति स्थापित कर दी थी। उच्च न्यायालय ने तब 'तालुकदारी संपत्ति' अभिव्यक्ति के अर्थ पर विचार किया और कहा कि इसका उपयोग वर्णनात्मक अर्थ में किया गया था और यह अभिव्यक्ति तालुकदार की संपत्ति के समकक्ष नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा:

> "इसलिए, अभिव्यक्ति "तालुकदारी संपत्ति" एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें वे सभी भूमियाँ शामिल हैं जो एक समय में तालुकदार की थीं। कानून की नजर में, हालाँकि ज़मीनें तालुकदार द्वारा अलग कर दी गई थीं, फिर भी वे संपत्ति का हिस्सा थीं। इसलिए, यह अभिव्यक्ति तालुकदार द्वारा प्राप्त किसी विशेष हित के बजाय एक विशेष कार्यकाल को इंगित करने वाली अभिव्यक्ति है

> .... इसलिए, यदि याचिका की विषय-वस्तु भूमियाँ, किसी भी समय तालुकदार की थी, जिसे उन्होंने बाद में अलग कर दिया, तो उन्हें 1949 के अधिनियम में परिभाषा के अधीन लिया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि जब अधिनियम पारित किया गया था तो तालुकदार उन भूमियों में कोई हित नहीं था।"

हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार से सहमत हैं। "लाल-लिटि" भूमि के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं और गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रकट रूप से स्पष्ट है कि "लाल-लिटि" भूमियाँ वह भूमियाँ है जो तालुकदारी का हिस्सा है। संपत्ति, भले ही ऐसी ज़मीनों के लिए वास्तव में तालुकदार या सरकार को कोई 'जामा' का भुगतान नहीं किया जाता था। यहां गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 4, 5 और 22 का उल्लेख करना आवश्यक है। धारा 4 सरकार को किसी भी तालुकदारी राज्य के राजस्व सर्वेक्षण का निर्देश देने का अधिकार देती है; धारा 5 बताती है कि तालुकदारी संपत्ति के संबंध में सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बंदोबस्त रजिस्टर में क्या विवरण होंगे। इस तरह के विवरणों में से एक नाम और विवरण और प्रत्येक हस्तांतरिती और संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के प्रत्येक भारधारी के हित की प्रकृति और सीमा के साथ-साथ (i) कुल क्षेत्र जिस पर ऐसा हित फैला हुआ है; (ii) किराए या भू-राजस्व की राशि और प्रकृति, यदि कोई

हो, ऐसे अंतरिती और भारधारक आदि द्वारा देय या प्राप्य।" यह हमारे सामने विवादित नहीं है, और उच्च न्यायालय ने इसका उल्लेख किया है, कि गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 5 के तहत प्रश्नगत दो गांवों के संबंध में तैयार किए गए बंदोबस्त रजिस्टरों में अपीलकर्ताओं का हित उनके पास मौजूद लाल-लिटि भूमि को धंधुका तालुकदारी जागीर में शामिल दिखाया गया था। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि ये "लाल-लिटि" भूमि तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा थी, सिवाय इस प्रश्न के कि हस्तांतरण के बाद तालुकदार ने उनमें क्या हित, यदि कोई हो, बरकरार रखा। गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 22 भी इसी ओर इशारा करती है। इसमें बताया गया है कि तालुकदार की संपत्ति के "जामा" की गणना कैसे की जाएगी: इसमें कहा गया है कि ऐसी जागीर बनाने वाली भूमि के सर्वेक्षण आकलन का कुल योग, ऐसी कटौती को घटाकर, यदि कोई हो, जैसा कि सरकार प्रत्येक मामले में निर्देश देगी, "जामा" होगी। अपनी याचिका के साथ, अपीलकर्ताओं ने "क" चिह्नित एक अनुबंध प्रस्तुत किया: उस अनुबंध में, एक तालुकदारी संपत्ति के भीतर अपीलकर्ताओं की भूमि को दिखाने के अलावा, भूमि के प्रत्येक भूखंड के लिए देय "जामा" भी दिखाया गया था। इससे फिर पता चला कि चाहे "जामा" वास्तव में चुकाया जाए या नहीं, अपीलकर्ताओं के पास मौजूद "लाल-लिटि" भूमि तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा थी। हम तदनुसार मानते हैं कि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता अपने तर्क में सही नहीं हैं कि "लाल-लिटि"

भूमि तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा नहीं है और इसलिए, उन्मूलन अधिनियम के अर्थ में तालुकदारी भूमियाँ नहीं है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमें गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 31 में "ताल्लुकदार की संपत्ति" अभिव्यक्ति के अर्थ के रूप में बॉम्बे उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का हवाला दिया और तर्क दिया कि इसका मतलब तालुकदार द्वारा दी गई संपत्ति है और उसी सादृश्य पर, उन्होंने आग्रह किया कि तालुकदारी संपत्ति का हिस्सा बनने वाली भूमि का मतलब वह भूमि भी होना चाहिए जिसमें तालुकदार के पास तालुकदार के रूप में कुछ हित हों (खोड़ा भाई बनाम छगनलाल (1907) बॉम्बे एल.आर. 1122), बिचेसभा मानसंगजी बनाम वेला धनजी पटेल (1909) द्वितीय बॉम्बे एल.आर. 736) और तालुकदारी बंदोबस्त अधिकारी बनाम छगनलाल द्वारकादास (1910) 12 बॉम्बे एल.आर. 903 हमें नहीं लगता कि उन निर्णयों से अपीलकर्ताओं को कोई मदद मिलेगी क्योंकि साधारण कारण यह है कि सादृश्य लागू नहीं होता है; यहां हमारा संबंध गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 31 में आने वाली अभिव्यक्ति "ताल्लुकदार की संपत्ति" के अर्थ से नहीं है, बल्कि एक अलग अभिव्यक्ति के अर्थ से है, अर्थात, उन्मूलन अधिनियम की धारा 2(3) में "तालुकदारी संपत्ति"। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कुछ निर्णयों में, यह माना गया कि 'ताल्लुकदार की संपत्ति' और 'तालुकदारी संपत्ति' के बीच अंतर था।

हमें तालुकदार द्वारा जिलाधीश के पक्ष में अपनी जमीन छोड़ने के प्रभाव (नाथूराम हीराराम ठाकुर बनाम भारत के राज्य सचिव (1929) 32 बॉम्बे एल.आर. 907 या तालुकदार द्वारा मूल्यांकन का भुगतान करने में विफल रहने पर राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत गांव की कुर्की के प्रभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया (तुल्ला सुभार्नम पंड्या बनाम कैरा जिलाधीश (1918) 20 बॉम्बे एल.आर. 748) हमें नहीं लगता कि मौजूदा मामले में उन सवालों पर विचार करना जरूरी है।

अब हम अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए दूसरे बिंदु पर जाते हैं। इस मुद्दे पर न तो पहले आग्रह किया गया था और न ही उच्च न्यायालय द्वारा उस रिट आवेदन में इस पर विचार किया गया था जिसमें उसने अपना प्रमुख निर्णय दिया था। अपीलकर्ता अपने स्वयं के आवेदन पर उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर आग्रह करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि यदि रिट आवेदन संख्या 1098/1954 में उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था, तो इसे केवल इस न्यायालय द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। इस बिंदु पर तर्क, उन्मूलन अधिनियम की धारा 5(1) पर आधारित है, जिसे हमने पहले उद्धृत किया है, और दो भागों में है: सबसे पहले, यह तर्क दिया गया है कि यदि धारा (1) की उप-धारा के खंड (क) और (ख) को धारा 5 को एक साथ पढ़ा जाए तो एकमात्र उचित निष्कर्ष यह है कि खंड (क) घोषणात्मक है और खंड (ख) कार्यात्मक खंड है और उस कार्यात्मक खंड के अनुसार, जो व्यक्ति

भूमि राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनते हैं, वे केवल संख्या में दो हैं, अर्थात्, (1) तालुकदारी भूमि रखने वाला एक तालुकदार और (2) उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले भरण-पोषण के उद्देश्य से वंशानुगत अधिकारों के साथ तालुकदारी परिवार का कोई कैडेट, और इसलिए, "लाल-लिटि" भूमि के धारक, यह मानते हुए कि यह तालुकदारी भूमि है, धारा 5(1) के तहत कोई दायित्व नहीं है; दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि भले ही धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) को वितरणात्मक रूप से पढ़ा जाता है, फिर भी "लाल-लिटि" भूमि के धारक का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि खंड (क) तालुकदारी भूमि को राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है और उस संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत "लाल-लीती" धारक को भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।

हम पहले तर्क का पहला भाग लेते हैं। हमें उन्मूलन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) को कैसे पढ़ना चाहिए? अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि खंड (क) को एक खंड के रूप में भी पढ़ा जाता है जो सभी तालुकदारी भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान के दायित्व के साथ शुल्क लगाने के लिए संचालित होता है, तो खंड (ख) पूरी तरह से अनावश्यक अधिशेष बन जाता है।दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि यदि आशय केवल दो श्रेणियों के व्यक्तियों, तालुकदारों और कैडेटों पर दायित्व

थोपना था, तो खंड (क) वास्तव में अनावश्यक था। हमारा मानना है कि दोनों खंडों का एक ही अर्थ और उद्देश्य है। खंड (क) सभी तालुकदारी भूमि को राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है। उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 तालुकदारी कार्यकाल को समाप्त कर देती है और इसकी सभी घटनाओं को समाप्त कर देती है। यदि बिना किसी और बात के केवल तालुकदारी की अवधि को ही समाप्त कर दिया जाता तो एक शून्यता आ जाती। जाहिर तौर पर, यह कहना जरूरी था कि तालुकदारी अवधि के उन्मूलन के बाद तालुकदारी भूमि का क्या होगा। इसलिए, खंड (क) में कहा गया है कि सभी तालुकदारी भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी तो फिर खंड (ख) का क्या मतलब है? यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें तालुकदार और उसके कैडेट को राजस्व संहिता के अर्थ के तहत रहने वाला माना जाएगा; और 'राजस्व संहिता के तहत अधिभोगी का अर्थ है असंक्रमित भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाला धारक। राजस्व संहिता में 'अन्यसंक्रांत' शब्द का भी विशेष अर्थ है; इसका मतलब है कि जहां तक सरकार के किराए या भू-राजस्व के भुगतान के अधिकारों का संबंध है, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में हस्तांतरित कर दिया गया है।' खंड (ख) केवल उन्मूलन अधिनियम के तहत तालुकदार और उसके कैडेट की स्थिति को स्पष्ट करता है; यह किसी भी तरह से खंड (क) का अल्पीकरण नहीं करता है; न ही यह खंड (क) के की व्यापकता में

कटौती करता है। हमारा विचार है कि खंड (क) और (ख) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए अर्थ में नहीं। खंड (ख) व्यक्तियों की दो श्रेणियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करता है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि तीसरी श्रेणी के व्यक्ति उचित रूप से खंड (क) के अंतर्गत आते हैं, वे एक विशिष्ट और अनुचित अवधारणा पर भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे कि खंड '(ख) परिचालन खंड के रूप में खंड (क) की व्यापकता को कम कर देता है। खंड (क) का सही दृष्टिकोण यह है कि खंड (क) एक सामान्य प्रावधान है और राजस्व संहिता को सभी तालुकदारी भूमि पर लागू करता है, जबकि खंड (ख) तालुकदार और उसके कैडेट के संबंध में एक विशेष प्रावधान है।

अब, जहां तक तर्क के दूसरे भाग की बात है, यहां राजस्व संहिता की धारा 136(1) को पढ़ना आवश्यक है:

> "धारा 136 (1): असंबद्ध भूमि के मामले में अधिभोगी, और हस्तांतरित भूमि या तालुकदारी भूमि के मामले में, वरिष्ठ धारक, भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का, सभी बकाया सहित भू-राजस्व के भुगतान के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। संयुक्त अधिभोगी और संयुक्त धारक जो इस धारा के तहत मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।"

प्रश्न यह है कि क्या "लाल-लिटि" भूमि का धारक, उन्मूलन अधिनियम के बाद, धारा 136 के अर्थ के अंतर्गत असंक्रमित भूमि का अधिभोगी है; यदि वह है, तो वह राजस्व संहिता की धारा 136 सपठित धारा 5(1)(क) उन्मूलन अधिनियम के तहत भू-राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। इस प्रश्न से निपटने में, जिसने हमें कुछ चिंता में डाल दिया है, हमें राजस्व संहिता में प्रयुक्त 'अधिभोगी' और 'अन्यसंक्रांत करना' शब्दों के अर्थ को याद रखना चाहिए। अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि "लाल-लिटि" धारक असंक्रमित भूमि का रहने वाला नहीं है; उत्तरदाताओं का तर्क है कि वह उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद है। प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाताओं का तर्क सही है।

"लाल-लिटि" भूमि के संबंध में, सरकार ने ऐसी भूमि के धारकों के साथ कोई अलग समझौता नहीं किया; समझौता तालुकदार के साथ किया गया था, जिसके अंतर्गत समझोते में "लाल-लिटि" भूमि भी शामिल थी। भू-राजस्व के भुगतान का सरकार का अधिकार कभी भी "लाल-लिटि" भूमि धारक को हस्तांतरित नहीं किया गया, हालांकि यह सच है कि लाल-लिटि भूमि के लिए, कुछ तालुकदारों को गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 22 के तहत छूट मिली थी। हमें विस्तार से बताया गया है कि उन्मूलन अधिनियम से पहले तालुकदारों और "लाल-लिती" धारकों की स्थिति क्या थी। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है

कि तालुकदारी अवधि की एक विशेषता यह थी कि तालुकदारी संपत्ति राजस्व संहिता के अर्थ के भीतर न तो अन्यसक्रांत की गई थी और न ही अन्यसक्रांत नहीं गई थी; क्योंकि तालुकदार ब्रिटिशों के अनुदानग्राही नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भी उन्हें अपनी सम्पदा में मालिकाना अधिकार प्राप्त था। जहां तक "लाल-लिटि" भूमि का संबंध है, तालुकदारों द्वारा सरकार को देय "जामा" की गणना करते समय आम तौर पर उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाता था; और परिणामस्वरूप, वे तालुकदार के पक्ष में लागू होने वाली निपटान गारंटी के दायरे में नहीं आते थे। इसलिए, उत्तरदाताओं की ओर से तर्क आगे बढ़ा, "लाल-लिटि" भूमि के धारक इस आधार पर पूर्ण मूल्यांकन के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो गए हैं कि वे उन्मूलन अधिनियम प्रवर्तन में आने की तारीख से पहले वे अन्यसक्रांत भूमि के अधिभोगी बन गए हैं। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में उन्मूलन अधिनियम की अनुसूची-1 द्वारा राजस्व संहिता में किए गए संशोधनों की सूची पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। राजस्व संहिता की धारा 136 और अन्य धाराओं में आवश्यक संशोधन करके तालुकदारों और सभी तालुकदारी भूमियों को राजस्व संहिता की योजना में लाया गया है।

हमारे सामने संकीर्ण प्रश्न यह है, जैसा कि हमने पहले कहा है, क्या "लाल-लिटि" धारक राजस्व संहिता के अर्थ के तहत ' अनन्यसंक्रामित भूमि' का 'अधिभोगी' है। हमारा मानना है कि उन्मूलन अधिनियम द्वारा तालुकदारी कार्यकाल

के उन्मूलन पर पहले उनकी स्थिति चाहे जो भी रही हो, वह उस भूमि का वास्तविक कब्ज़ा धारक बन गया जिसके संबंध में सरकार ने राजस्व के भुगतान के अपने अधिकारों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में स्थानांतरित नहीं किया था।

इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया दूसरा बिंदु दोनों भागों में विफल रहता है।

हमें अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए तीन अन्य बिंदुओं पर भी संक्षेप में ध्यान देने की आवश्यकता है; क्योंकि हम उनके संबंध में उच्च न्यायालय के साथ पूरी तरह सहमत हैं, इसलिए उन कारणों को विस्तार से बताना अनावश्यक है जो उच्च न्यायालय-पहले ही बता चुका है।

(1) उन्मूलन अधिनियम की धारा 17 के व्यावृत्ति खंड (ग) के संबंध में, उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया है कि यह सामान्य व्यावृत्ति खंड है जो प्रभावी रूप से कहता है कि गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 के निरसन को उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई किसी भी घोषणा या मान्यता प्राप्त किसी करार या समझौते आदि को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। उपरोक्त व्यावृत्ति खंड उन्मूलन अधिनियम की धारा 5 द्वारा अधिरोपित गए दायित्व के विरुद्ध कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

(2) विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे व्यक्तिगत इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1952 (1953 का बॉम्बे अधिनियम 42) द्वारा निरस्त किए जाने से पहले, उन्मूलन अधिनियम की धारा 5(2)(क) पर भी भरोसा किया और उस पर अपना वैकल्पिक दावा आधारित किया। यहां फिर से, उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया कि अपीलकर्ताओं के पक्ष में भू-राजस्व के भुगतान से छूट के संबंध में कोई विशेष अनुबंध नहीं था और न ही उन्मूलन अधिनियम के बाद कुछ समय के लिए कोई कानून लागू था जो 'लाल लिती' धारक को छूट प्रदान करता था।; इसलिए, अपीलकर्ता 1 अगस्त,1953 तक उन्मूलन अधिनियम की धारा 5(2)(क) के तहत किसी सुरक्षा के हकदार नहीं थे।

(3) अंत में, यह तर्क दिया गया कि 1925-26 में प्रश्नगत तालुकदारी संपत्ति के साथ तीस वर्षों के लिए एक समझौता हुआ था और राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी नए समझौते के अभाव में, एक "लाल-लिटि" धारक उस अवधि के भीतर भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस बिंदु का उत्तर उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 द्वारा पूरी तरह से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 की धारा 4 के तहत तालुकदारी सम्पदा के सभी राजस्व सर्वेक्षण या संशोधित राजस्व सर्वेक्षण और किए गए सभी समझोते राजस्व संहिता के अध्याय VIII और VIIIA के तहत किए गए माने जाएंगे और ऐसे सर्वेक्षणों में तैयार किए गए निपटान रजिस्टर और अन्य अभिलेख राजस्व संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए माने जाएंगे। हम जानते हैं कि इस

मामले की "लाल-लीती" भूमि को गुजरात तालुकदार अधिनियम, 1888 के तहत तैयार किए गए निपटान रजिस्टरों में दिखाया गया था। उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर, कोई नया समझौता आवश्यक नहीं था।

ऊपर दिए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत है। तदनुसार अपील हर्जे-खर्चे सहित खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक (विनोद कुमार उज्जैनिया) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।